करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

जुलाई 2022

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश में बृहद् ऋण मेले का शुभारंभ 3
- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 4
- संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ 4
- उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कांक्लेव, 2022 4
- बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर-19 में नोएडा के नीर और चिराग पुरुष एकल में बने चैंपियन 5
- स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर 5
- वन महोत्सव अभियान 6
- यूपी के विज़नरी यूथ को ब्लॉकों में फेलोशिप 6
- उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2022 7
- उत्तर प्रदेश पुरोहित कल्याण बोर्ड एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली 8
- 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर 8
- प्रधानमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया 9
- प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर बनेगी अनूठी रिवर आर्ट गैलरी 9
- उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन 9
- 130 किमी./घंटा की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में प्रयागराज मंडल देश में नंबर वन 10
- उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरियारोधी पौधे की खेती कराने की तैयारी 11
- नोएडा में तीन हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अपैरल पार्क 11
- प्रधानमंत्री ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 12
- मदरसों में दाखिले की न्यूनतम उम्र तय करने के लिये राज्य सरकार बनाएगी समिति 12
- सारस के लिये बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूज़ियम 13
- इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला सातवाँ स्थान 13
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना'का शुभारंभ 14
- उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये निर्यात पर ज़ोर 14
- बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा 15
- उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये निर्यात पर ज़ोर 15
- बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा 16
- हिरासत में हुई मौतों में उत्तर प्रदेश अव्वल 16
- 'एक तहसील एक उत्पाद'योजना 17
- प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिये स्टेशनरी फ्री, बैंक अकाउंट में मिलेंगे अब 1200 रुपए 17
- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना 18
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप 'कू' के बीच एमओयू 18
- उत्तर प्रदेश में पाँच साल का रोडमैप तैयार, 66 लाख महिलाओं को रोज़गार से जोड़ेगी राज्य सरकार 19
- उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच हुआ एमओयू 19

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में बृहद् ऋण मेले का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

30 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित समारोह में बृहद् ऋण मेले का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को दिये गए ऋण का प्रतीकात्मक चेक सौंपा।
- सभी 75 जनपदों में आयोजित बृहद् ऋण मेले के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम', 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना', 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना', 'एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना' आदि के 1 लाख 90 हजार लाभार्थी हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया गया।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वर्ष 2022-23 की 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का विमोचन किया साथ ही कार्यक्रम के दौरान 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के अंतर्गत 5 जनपदों-आगरा, अंबेडकरनगर, सीतापुर, आजमगढ़, सिद्धार्थ नगर में स्थापित कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया।
- कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना से 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को आधुनिक तकनीकी से जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी और आय में वृद्धि होगी।
- मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल एवं अमेजॉन के वीपी पॉलिसी चेतन कृष्ण स्वामी के मध्य एक एमओयू का आदान-प्रदान किया गया। इसके तहत अमेजॉन छोटी इकाइयों को अपने उत्पादों के निर्यात में सहायता करेगा। अमेजॉन छोटी इकाइयों को डिजिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिये अमेजॉन द्वारा कानपुर में एक डिजिटल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह गुजरात राज्य के सूरत के बाद अमेजॉन द्वारा देश में स्थापित दूसरा केंद्र होगा।
- ज्ञातव्य है कि कानपुर में अमेजॉन के डिजिटल केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से एमएसएमई हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों को देश-विदेश में अपने उत्पादों की मार्केटिंग में सहूलियत होगी।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश के 35 जनपदों में सिडबी के सहयोग से स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। यह केंद्र नये उद्यमियों की हैंड होल्डिंग का कार्य करेंगे। भविष्य में प्रदेश के सभी जनपदों में यह केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बृहद् ऋण मेले का कार्यक्रम एमएसएमई विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना का हिस्सा है। एमएसएमई उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियाँ तेजी से आगे बढ़ेंगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही, बैंकों का सी.डी. रेशियो भी बढ़ेगा।
- उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी, 2018 को 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' लागू की गई। वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का हब बनाकर नई पहचान दिला रही है। वर्ष 2016 में प्रदेश से लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का निर्यात होता था, जो अब बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इससे वर्तमान में प्रदेश की बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत से कम है।
- एमएसएमई मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वार्षिक ऋण योजना 2020-21 के तहत 2 लाख 12 हजार 934 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। एमएसएमई क्षेत्र में 83,061 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है, जो वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष 115 प्रतिशत है। वार्षिक ऋण योजना 2022-23 के अंतर्गत 2.95 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है।

नोट :

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने तात्कालिक प्रभाव से समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का प्रभार/दायित्व प्रदान किया है। इस संबंध में 29 जून, 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने अरुण यादव को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक यह पद सौंपा गया है।
- असीम अरुण 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2009 में अलीगढ़ में पहली बार स्वाट टीम का गठन किया। असीम अरुण हाथरस, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं।
- वे कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व ये आईपीएस की नौकरी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।
- भाजपा ने उन्हें कन्नौज सदर सीट से उम्मीदवार घोषित किया। यहाँ से असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी के लगातार तीन बार के विधायक अनिल दोहरे को हराकर जीत दर्ज की।
- 25 मार्च, 2022 असीम अरुण ने योगी कैबिनेट में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार पद की शपथ ली तथा 28 मार्च को उन्हें समाज कल्याण, एससी और एसटी मामलों की जिम्मेदारी दी गई।

संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

1 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही विशेष संचारी अभियान की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

प्रमुख बिंदु

- संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 जुलाई तक और इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया और चिकनगुनिया को फैलने से रोकने के लिये राज्य में घर-घर दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों पर 95 प्रतिशत तक नियंत्रण किया गया है और शेष 5 प्रतिशत को नियंत्रित कर राज्य से इस बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान के तहत आशा कार्यकर्त्ता, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के लोग घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और यदि कोई बीमार पाया जाता है, तो वे इलाज की व्यवस्था करेंगे और एक मेडिकल किट उपलब्ध कराएंगे।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कांक्लेव, 2022

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2022 को लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कांक्लेव, 2022 का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कांक्लेव की थीम '3R' (रियूज, रिसाइकिल व रिड्यूस) है।
- इस अवसर पर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री द्वारा आगरा के नगर आयुक्त निखिल टीकाराम को सम्मानित किया गया।
- गौरतलब है कि पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित अधिसूचित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया गया है।

नोट :

बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर-19 में नोएडा के नीर और चिराग पुरुष एकल में बने चैंपियन

चर्चा में क्यों ?

3 जुलाई, 2022 को आगरा में विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सेलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर-19 में नोएडा के नीर नेहवाल और पुरुष एकल वर्ग में नोएडा के ही चिराग सेठी चैंपियन बने।

प्रमुख बिंदु

- एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर-19 के फाइनल मैच में नोएडा के नीर नेहवाल ने नोएडा के ही हर्षित तोमर को 21-19, 21-10 से हराकर चैंपियनशिप पर कब्ज़ा किया।
- पुरुष एकल वर्ग का फाइनल मुकाबला नोएडा के चिराग सेठी ने प्रयागराज के प्रतीक श्रीवास्तव को 21-11, 21-08 से हराकर अपने नाम किया। पुरुष डबल्स फाइनल मुकाबले में सिद्धार्थ सालार और सिद्धार्थ मिश्रा की जोड़ी ने सहारनपुर के चंद्र भूषण त्रिपाठी और कपिल चौधरी की जोड़ी को हराकर खिताब जीता।
- उल्लेखनीय है कि बैडमिंटन एसोसिएशन आगरा द्वारा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े टूर्नामेंट विजय शर्मा मेमोरियल ईस्ट जोन सिलेक्शन का 30 जून से 3 जुलाई तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया था।
- बालिका वर्ग अंडर-19 के डबल्स में बस्ती की शिवांगी सिंह और तनीषा सिंह ने गोरखपुर और लखनऊ की आदित्या यादव व नेहल नीरू मित्तल की जोड़ी को 21-17, 21-13 से हराकर खिताब पर कब्ज़ा जमाया।
- महिला ओपन वर्ग में लखनऊ की समृद्धि सिंह और नोएडा की सोनाली सिंह ने गाज़ियाबाद और प्रयागराज की माही नरेश और मयूरी यादव को 21-13, 21-15 से हराकर ट्रॉफी पर कब्ज़ा किया।
- इस टूर्नामेंट में विजेता खिलाड़ियों के बीच एक लाख रुपए का पुरस्कार वितरित किया गया।
- टूर्नामेंट की अंडर-19 डबल्स प्रतियोगिता में आगरा के दक्ष गौतम व मेरठ के उज्ज्वल ने मुज़फ्फरनगर के शशांक और बरेली के उज्ज्वल तोमर की जोड़ी को 21-17, 21-18 से हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया।
- मिक्स डबल्स अंडर-19 फाइनल में आगरा के दक्ष गौतम और बस्ती की शिवांगी सिंह ने गोरखपुर के शिवम श्रीवास्तव व आदित्या यादव की जोड़ी को 21-19, 21-17 से हराया।
- ओपन मिक्स डबल्स में आगरा के आयुष अग्रवाल और गाज़ियाबाद की माही नरेश ने नोएडा के अभिनव शर्मा और रिद्धिमा सिंह को 21-18, 21-18 से हराया।

स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश लीडर

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के तीसरे संस्करण में उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- स्टार्टअप सुधारों से संबंधित 7 क्षेत्रों पर आधारित इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले
  - टॉप परफॉर्मर्स
  - लीडर्स
  - आकांक्षी लीडर्स
  - उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम।

नोट :

- रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे अर्थात् सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। टॉप परफॉर्मेंस वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना को शामिल किया गया है।
- वहीं लीडर्स श्रेणी में उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड, पंजाब, असम तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों को शामिल किया गया है, जबकि आकांक्षी लीडर्स की श्रेणी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि का चयन किया गया है।
- उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में आंध्र प्रदेश और बिहार शामिल हैं।

वन महोत्सव अभियान

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम सेहरिन गाँव स्थित कोदंड वन क्षेत्र में हरीशंकरी के पौधे रोपकर वन महोत्सव अभियान की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती व बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा किनारे वाले ज़िलों में यह प्रयोग सफल रहा है। अन्ना मवेशियों की समस्या से निदान दिलाया जाएगा। इसके साथ ही गाय के गोबर व गोमूत्र से कीटनाशक तैयार किया जाएगा, जिसका प्रयोग खेती में होगा।
- उल्लेखनीय है कि इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य है। इसमें एक दिन में (5 जुलाई) को 25 करोड़ पौधे रोपे गए तथा 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे।
- प्रदेश में 7 लाख सहजन के पौधे नि:शुल्क देकर पीएम व सीएम आवासों के सामने लगाए जाएंगे। विदित है कि चित्रकूट में टाइगर रिज़र्व पार्क बनाया जा रहा है, जहाँ टाइगर्स को लाया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वन क्षेत्र में बसे गाँवों को जल्द एनओसी देकर विस्थापित करें और शहर से गाँव को जोड़ने का काम करें। विकास के कामों के लिये एनओसी या विवाद के मामले हों तो उन्हें प्राथमिकता से निपटाएँ।

यूपी के विज़नरी यूथ को ब्लॉकों में फेलोशिप

चर्चा में क्यों ?

5 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के अधिकारियों को प्रदेश के ब्लॉकों में विकास की रफ्तार तेज करने के लिये विज़नरी यूथ की सेवाएँ लेने हेतु नियमावली बनाने के निर्देश दिये।

प्रमुख बिंदु

- इसके अंतर्गत विकास खंडों के विकास के लिये विज़नरी यूथ को 2 साल की विशिष्ट फेलोशिप के ज़रिये मौका मिलेगा।
- मुख्यमंत्री ने प्रत्येक नगर निगम में आगे की योजना बनाने के लिये टाउन प्लानर की नियुक्ति का आदेश दिया है। उन्हें 2 साल की फेलोशिप मिलेगी।
- इसके साथ ही वारिस के नाम प्रापर्टी ट्रांसफर या गिफ्ट डीड करने के मामले में दाखिल-खारिज़ पर अब क्रमश: 5 हज़ार रुपए और 10 हज़ार रुपए ही शुल्क देना होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित के लिये विकास प्राधिकरणों में संपत्ति के नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया का सरलीकरण ज़रूरी है। मौजूदा समय संपत्ति की कुल कीमत का म्यूटेशन शुल्क एक फीसदी लिया जा रहा है। इसे कम करने की ज़रूरत है। मौजूदा प्रक्रिया भी काफी जटिल है, इसे तकनीक के सहयोग से व्यावहारिक बनाया जाए।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षात्मक विकास खंडों के उचित विकास के लिये विशिष्ट फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किये जाने के निर्देश दिये। यह फेलोशिप दो वर्ष के लिये होगी। इसमें तकनीकी, प्रबंधन डिग्रीधारी विज़नरी युवाओं को तैनात किया जाएगा।

- इसमें युवाओं का चयन पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम किया जाएगा। अच्छी मासिक धनराशि दी जाएगी। इन्हें टैबलेट, स्मार्टफोन आदि तकनीकी उपकरण भी दिये जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल और अंबार शुल्क की दरें हर साल तय की जाएं। इसके लिये आयकर विभाग के कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स को आधार बनाया जाए।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फ्री होल्ड या गिफ्ट की जाने वाली संपत्ति के मूल्य के आधार पर अधिकतम 10,000 रुपए म्यूटेशन शुल्क लिया जाए। लीज संपत्ति की स्थिति में एक फीसदी म्यूटेशन फीस ली जा सकती है।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विकास प्राधिकरणों द्वारा निवासियों से जल शुल्क लेने की व्यवस्था की जाए। अधिकांश विकास प्राधिकरणों में जल शुल्क नहीं लिया जा रहा है। लखनऊ व वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर निर्धारित शुल्क पर जल शुल्क लिया जा रहा है। इसके लिये नियमावली बनाई जाए।
- मुख्यमंत्री ने लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर का काम दो माह में शुरू करने का निर्देश दिया। यह योजना लखनऊ को एक आकर्षक स्वरूप देने वाली होगी। गोमती नदी के दोनों तटों और नैमिषारण्य अतिथि भवन के आसपास कुछ झुग्गी बस्तियाँ हैं। इनका चिह्नीकरण कर यहाँ के निवासियों को कहीं और बसाया जाए।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बटलर झील को अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाए। विकास प्राधिकरण, नगरीय निकाय, प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियाँ व रिहायशी कॉलोनी न बसने पाए।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 को बेसलाइन मानते हुए चयनित इंडिकेटर पर ब्लॉकवार सूचना वर्तमान माह के अंत में एकत्रित कर ली जाए। इसके बाद प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संबंधित ज़िलों द्वारा ताजा प्रगति विवरण फीड की जाए। इसकी पुष्टि संबंधित विभागों द्वारा भी कराई जाए। इसकी प्रगति को सीएम डैशबोर्ड से भी जोड़ा जाए।

उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2022

चर्चा में क्यों ?

4 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्प ग्राम, लखनऊ में चारदिवसीय 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2022' का शुभारंभ किया। यह महोत्सव 7 जुलाई, 2022 तक आयोजित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- आम महोत्सव के माध्यम से आम के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, निर्यात एवं गुणवत्ता में वृद्धि के सभी आयामों पर संबंधित विभागों/अधिकारियों/वैज्ञानिकों द्वारा आम उत्पादकों के साथ विचार-विमर्श करते हुए उन्हें जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- महोत्सव में आम के प्रसंस्कृत उत्पाद एवं पौधे भी बिक्री के लिये उपलब्ध होंगे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि हर साल पहली से 7 जुलाई के बीच आम महोत्सव आयोजित किया जाए और इसमें देश के विभिन्न राज्यों के आम के बागवानों को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित भी किया जाए।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आम का मेगा क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की। यह परियोजना अगले पाँच वर्षों में पूरी होगी। इस परियोजना के लिये केंद्र से 100 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है।
- उन्होंने कहा कि अब लखनऊ में माल, मलिहाबाद और काकोरी फलपट्टी का आम देश और विदेश में काकोरी आम के नाम से भेजा जाएगा। इसी नाम से लखनऊ के आम की ब्रॉन्डिंग होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार ने लखनऊ के आम की ब्रॉन्डिंग नवाब आम के नाम से की थी।

नोट :

उत्तर प्रदेश पुरोहित कल्याण बोर्ड एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली

चर्चा में क्यों?

6 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन एवं एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली शुरू करने के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश दिये गए।

प्रमुख बिंदु

- लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022 की घोषणा के अनुरूप बुजुर्ग संतों, पुरोहितों एवं पुजारियों के कल्याण के लिये पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- इस बोर्ड के अंतर्गत मौलवियों को भी शामिल करते हुए सभी धर्मों के संतों एवं पुजारियों का चिह्नांकन एवं सत्यापन जल्द किया जाएगा।
- धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली की शुरुआत की जाएगी, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि धार्मिक संप्रदायों से जुड़े धर्मस्थलों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसी प्रकार मस्जिदों के बारे में भी एक विशिष्ट पोर्टल बनाया जाएगा, जिसे बाद में एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा।

'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

5 जुलाई, 2022 को जारी 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में ओडिशा पहले स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' का पहला संस्करण जारी किया।
- सामान्य श्रेणी के राज्यों में 'एनएफएसए के लिये राज्य रैंकिंग सूचकांक' में ओडिशा 836 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 0.797 स्कोर के साथ दूसरे और आंध्र प्रदेश 0.794 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में त्रिपुरा 788 स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 0.758 स्कोर के साथ दूसरे और सिक्किम 0.710 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।
- इसके अलावा तीन केंद्रशासित प्रदेशों में, जहाँ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) नकद संचालित है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव 802 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर हैं।
- यह सूचकांक राज्यों के साथ परामर्श के बाद देश भर में एनएफएसए के कार्यान्वयन और विभिन्न सुधार पहलों की स्थिति और प्रगति का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करता है।
- यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किये गए सुधारों पर प्रकाश डालता है तथा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एक क्रॉस-लर्निंग वातावरण और स्केल-अप सुधार उपायों का निर्माण करता है।
- वर्तमान सूचकांक काफी हद तक एनएफएसए वितरण पर केंद्रित है और इसमें भविष्य में खरीद, पीएमजीकेएवाई वितरण शामिल होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिये सूचकांक तीन प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है, जो टीपीडीएस के माध्यम से एनएफएसए के एंड-टू-एंड कार्यान्वयन को कवर करता है। ये स्तंभ हैं- i) एनएफएसए- कवरेज, लक्ष्यीकरण और अधिनियम के प्रावधान, ii) डिलीवरी प्लेटफॉर्म, और iii) पोषण संबंधी पहल।

नोट :

प्रधानमंत्री ने 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों?

7 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के सिगरा स्थित डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 590 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें वाराणसी स्मार्ट सिटी एवं शहरी परियोजनाओं के तहत आने वाली कई पहल शामिल हैं।
- इसी तरह प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें सड़क अवसंरचना से जुड़ी विभिन्न परियोजनाएँ शामिल हैं। इन परियोजनाओं से शहर और ग्रामीण सड़कों पर यातायात के भार को कम करने में काफी मदद मिलेगी।
- इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 'उत्तर प्रदेश गरीब समर्थक पर्यटन विकास परियोजना' के तहत सारनाथ बौद्ध सर्किट के विकास कार्य, अष्टविनायक के लिये पवनपथ का निर्माण, द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा, अष्टभैरव, नवगौरी यात्रा, पंचकोसी परिक्रमा यात्रा मार्ग में पाँच पड़ावों के पर्यटन विकास कार्य और पुरानी काशी में विभिन्न वार्डों में पर्यटन विकास के कार्य सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सिगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्विकास कार्यों के प्रथम चरण का शिलान्यास भी किया।

प्रयागराज में एफिल टावर की तर्ज पर बनेगी अनूठी रिवर आर्ट गैलरी

चर्चा में क्यों?

8 जुलाई, 2022 को एनएचएआई के परियोजना निदेशक नुसरतुल्लाह ने बताया कि एफिल टॉवर की तर्ज पर प्रयागराज में गंगा किनारे निर्माणाधीन सिक्स लेन पुल के टॉवर पर रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। इसका प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह देश की इकलौती ऐसी रिवर गैलरी होगी, जहां कुंभ और प्रयागराज की संस्कृति की छटा से देश-दुनिया के सैलानी सीधा साक्षात्कार कर सकेंगे। इस रिवर गैलरी में प्रयागराज के अतिरिक्त नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में लगने वाले कुंभ की छटा को भी दिखाया जाएगा।
- प्रयागराज में प्रवेश करने से पूर्व ही सैलानी इस गैलरी में आकर आध्यात्मिक नगरी की संस्कृति और विरासत के साथ ही कला की झलक ले सकेंगे। शंकराचार्यों और अखाड़ों के नागा संन्यासियों की पेंटिंग और उनकी भक्ति-भावना और ध्यान-तप आदि से भी पर्यटक यहाँ परिचित हो सकेंगे।
- फाफामऊ में दो हजार करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन 10 किमी. लंबे सिक्स लेन सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ से पूर्व ही पूरा कर लिया जाएगा।
- इस रिवर आर्ट गैलरी में पहुंचने के लिए दोनों तरफ कैप्सूल लिफ्ट लगाया जाएगा। गैलरी के दूसरी तरफ एक रिवाल्विंग रेस्तरां बनाने का भी प्रस्ताव है।

उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

10 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बने उत्तर भारत के सबसे बड़े 'लुलु मॉल' का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस मॉल का निर्माण सुशांत गोल्फ सिटी में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्गफीट में किया गया है। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ बना प्रदेश का सबसे बड़ा हाइपर मार्केट और गेमिंग ज़ोन हैं। इसके अलावा शादियों की खरीदारी के लिये वेडिंग एरीना और मनोरंजन के लिये 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स भी यहाँ तैयार किया गया है।
- यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों व सुविधाओं के साथ देश-विदेश के ब्रॉण्ड के सामान की खरीदारी की जा सकेगी। मॉल के अंदर 15 रेस्टोरेंट, 25 आउटलेट के साथ 1600 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ बना फूड कोर्ट भी है। यहाँ 3,000 वाहनों की पार्किंग क्षमता है। वहीं 50 हज़ार लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं।
- पर्यटकों को शटल सेवा उपलब्ध कराने पर भी कंपनी विचार कर रही है। यहाँ ग्रॉसरी से लेकर फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोरेशन का सामान भी उपलब्ध है।
- यह लुलु समूह का पाँचवा शॉपिंग मॉल है। कंपनी प्रयागराज और वाराणसी में भी नए शॉपिंग मॉल पर काम कर रही है। रिटेल प्रोजेक्ट्स के अलावा लुलु समूह ने फूड प्रोसेसिंग हब की भी घोषणा की है, जो करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है।

130 किमी./घंटा की रफ्तार से सर्वाधिक ट्रेनें चलाने में प्रयागराज मंडल देश में नंबर वन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रेलवे अफसरों ने बताया कि उत्तर-मध्य रेलवे (एनसीआर) का प्रयागराज मंडल देश का पहला ऐसा मंडल बन गया है, जहाँ संचालित 338 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में 272 की अधिकतम स्पीड अब 130 किमी. प्रति घंटा हो गई है। यह आँकड़ा भारतीय रेल के सभी 68 रेल मंडलों में सर्वाधिक है।

प्रमुख बिंदु

- रेलवे अफसरों का दावा है कि वर्ष 2025 में लगने वाले कुंभ मेले के पूर्व प्रयागराज मंडल में चल रहीं तमाम ट्रेनों की स्पीड 160 किमी. प्रति घंटा हो जाएगी।
- गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व प्रयागराज मंडल क्षमता से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन और रेलवे के आधारभूत ढाँचे के सुधार की धीमी गति की वजह से ट्रेनों की लेटलतीफी के लिये बदनाम था।
- कोविड की पहली लहर के दौरान लॉकडाउन में यात्री ट्रेनों के बंद हो जाने पर एनसीआर के तीनों मंडलों में आधारभूत ढाँचा सुधारने के लिये तेज़ी से काम हुआ। इस दौरान जहाँ एक ओर अलीगढ़, इटावा, खुर्जा, टुंडला, जुही कानपुर यार्ड आदि की रिमॉडलिंग हुई, तो वहीं दूसरी ओर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम भी तेज़ी से हुआ।
- पुरानी रेल पटरियों के स्थान पर नई पटरियाँ बिछाई गईं। इस बीच ज़ोन की बहुत-सी ट्रेनों में लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) कोच भी लगाए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सिर्फ प्रयागराज मंडल के ही सात खंडों में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और 14 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य पूरा किया गया। इससे ट्रेनों की लेटलतीफी में भी सुधार हुआ।
- प्रयागराज मंडल के साथ ही एनसीआर ज़ोन में चलने वाली कुल 520 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 130 किमी. प्रति घंटा हो गई है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 14 और ट्रेनों की अधिकतम स्पीड 130 किमी. प्रति घंटा हो गई है।
- प्रयागराज मंडल में 160 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार तक ट्रेन चलाने के लिये यहाँ गाज़ियाबाद से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन तक रेलवे ट्रैक के दोनों ओर दीवार भी बनाई जा रही है, ताकि रेलवे ट्रैक पर मवेशी आदि न आ सकें, क्योंकि उनके ट्रेन की चपेट में आने की वजह से रूट बाधित हो जाता है। यह दीवार भी वर्ष 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए।

उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरियारोधी पौधे की खेती कराने की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

13 जुलाई, 2022 को लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीमैप) के निदेशक प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरियारोधी पौधे आर्टिमिसिया की नई प्रजाति सीआईएम-संजीवनी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिये नई नीति का मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- सीमैप ने उत्तर प्रदेश सहित देशभर में मलेरियारोधी पौधे आर्टिमिसिया की नई प्रजाति सीआईएम-संजीवनी की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिये चेन्नई की कंपनी सत्तव वैद नेचर्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से अनुबंध किया है।
- यह कंपनी आर्टिमिसिया की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी। साथ ही प्रसंस्करण से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान देगी। कंपनी तैयार पौधों को किसान से लेकर दवा बनाने वाली कंपनियों तक पहुँचाएगी। इससे किसानों को उनकी उपज की कीमत खेत में ही मिल जाएगी।
- इससे एक तरफ मलेरिया की दवा बनाने के लिये विदेश से कच्चा माल नहीं मँगाना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ किसानों को भी फायदा मिलेगा।
- निदेशक प्रबोध कुमार त्रिवेदी ने बताया कि कई वर्षों के शोध के बाद नई प्रजाति विकसित की गई है। यह पहले से चल रही किस्म जीवन रक्षा और सीआईएम आरोग्य के बीच पॉली क्रास से विकसित की गई है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीडीआरआई) ने भी अपने शोध में इस पौधे को मलेरियारोधी दवा के लिये उपयुक्त माना है।
- प्रदेश में 2027 तक मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। कई ज़िलों में पिछले साल से एपीआई (एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस) की दर एक से नीचे मिली है। जून 2022 तक 26 लाख 77 हज़ार से अधिक सैंपल की जाँच की गई, जिसमें 1077 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं।
- उल्लेखनीय है कि आर्टिमिसिया पौधे में आर्टीमिसनिन नामक तत्त्व पाया जाता है, जिससे मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। आर्टीमिसनिन मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु प्लास्मोडियम फाल्सीपैरम को खत्म कर देता है। यह पौधा आमतौर पर चीन में पाया जाता है। वहाँ से इसे भारत लाकर नई-नई प्रजाति तैयार की जा रही हैं। इस पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर) के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट (सीमैप) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों ने प्रयोग किये हैं।
- सीमैप के वैज्ञानिकों ने आर्टिमिसिया की नई प्रजाति सीआईएम-संजीवनी में आर्टीमिसिनिन तत्त्व 2 फीसदी अधिक पाया। इस प्रजाति में मस्तिष्क ज्वर के साथ कैंसर सहित अन्य बीमारियों में प्रयोग होने वाली दवा बनाने वाले तत्त्व भी अधिक हैं। इससे खाने की गोली व इंजेक्शन तैयार किये जाते हैं।
- जर्नल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमैटिक प्लांट साइंसेज में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि सीआईएम-संजीवनी किसानों और खेती से जुड़े उद्योग के लिये भी फायदेमंद है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस पौधे से दवा बनाने वाली कंपनी करीब 20 फीसदी लागत घटा सकती है।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आर्टिमिसिया की खेती से किसानों को लगभग चार माह की अवधि में प्रति हेक्टेयर करीब 65 हज़ार रुपए का फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि इस पौधे को लेकर भारतीय कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने के लिये आगे आ रही हैं।

नोएडा में तीन हज़ार करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अपैरल पार्क

चर्चा में क्यों ?

15 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कहा कि नोएडा में तीन हज़ार करोड़ रुपए की लागत से अपैरल पार्क स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इसमें 115 वस्त्र इकाइयाँ स्थापित की जाएगी और 2 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमएसएमई विभाग की 100 दिन की उपलब्धियाँ बताते हुए राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा से पावरलूम संचालन को प्रोत्साहित करने के लिये 'मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना' के नाम से एक नई योजना शुरू की जाएगी।

नोट :

- इससे पारंपरिक विद्युत ऊर्जा की खपत कम होगी। प्रदूषण में कमी के साथ वस्त्र उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी और बुनकरों को आर्थिक लाभ होगा।
- टैक्सटाइल पॉलिसी-2017 में नवाचार को शामिल करते हुए टेक्सटाइल पॉलिसी-2022 का ड्राफ्ट तैयार करके शासन को भेजा गया है। नई पॉलिसी से प्रदेश में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में निवेश में और अधिक बढ़ोतरी होगी तथा अधिकारिक रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि 30 जून, 2022 को आयोजित मेगा लोन मेले में 1 लाख 90 हज़ार लाभार्थियों को 16 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। एमएसएमई अधिनियम के तहत 100 दिनों में 73 उद्यम स्थापित हो चुके हैं। अब तक 7202 उद्यम अधिनियम के तहत स्थापित हुए है।

प्रधानमंत्री ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

16 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे के ज़रिये दिल्ली से जुड़ गया है।
- इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज़्यादा ज़्यादा छोटे पुल, 15 से ज़्यादा फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा और 12 से ज़्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य में यह चौथी एक्सप्रेसवे परियोजना है, जो रिकॉर्ड 28 महीने में पूरी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को इस परियोजना की नींव रखी थी।
- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के तत्त्वावधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस 296 किलोमीटर फोर-लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। बाद में इसे छह लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास गोंडा गाँव में NH-35 से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरैल गाँव तक फैला हुआ है, जहाँ यह आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है।
- यह सात जिलों- चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है।
- क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों के लिये हजारों नौकरियों का सृजन होगा।

मदरसों में दाखिले की न्यूनतम उम्र तय करने के लिये राज्य सरकार बनाएगी समिति

चर्चा में क्यों?

16 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि राज्य के मदरसों में दाखिले के लिये न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करने को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) समेत विभिन्न शिक्षा परिषदों की तर्ज़ पर राज्य के मदरसों में भी दाखिले के लिये न्यूनतम आयु सीमा तय करेगी।
- इसी के साथ उन्होंने छात्रों की अधिकतम आयु सीमा तय करने पर विचार किये जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मदरसों में दाखिले के लिये अधिकतम उम्र तय करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

नोट :

- प्रदेश के मदरसा शिक्षकों के संगठन 'टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश' के महासचिव दीवान साहब जमां खाँ ने बताया कि राज्य के मदरसों में कक्षा एक में प्रवेश के लिये छात्रों की न्यूनतम आयु पाँच साल और कक्षा 10 में दाखिले के लिये न्यूनतम आयु 14 साल पहले से ही निर्धारित है।
- उत्तर प्रदेश में 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान प्राप्त होता है। अनुदान के अंतर्गत मदरसों के शिक्षकों और गैर-शिक्षणकर्मियों को वेतन-भत्ते का भुगतान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि मई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से पेश किये गए प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया कि राज्य में अब नए मदरसों को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा।

सारस के लिये बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूज़ियम

चर्चा में क्यों ?

20 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में हुई शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान समिति की बैठक में उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिये बाड़ा और स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूज़ियम बनाने का निर्णय लिया गया।

प्रमुख बिंदु

- शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान में प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस के लिये 25 लाख रुपए से बाड़ा बनाया जाएगा। रेस्क्यू किये गए सारस को चिड़ियाघर में रखा जाएगा।
- इसके अलावा बैठक में 25 लाख रुपए की लागत से इंटरपिटेशन सेंटर के विकास को भी मंज़ूरी दी गई, जहाँ अन्य कार्यों के साथ स्टफ वाइल्ड एनिमल म्यूज़ियम का निर्माण किया जाएगा।
- बैठक में प्राणी उद्यान के निदेशक डॉ. एच. राजा मोहन ने बताया कि सारस का बाड़ा बनाने के लिये केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण को पत्र भेजकर अनुमति मांगी जाएगी।
- 121 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस प्राणी उद्यान में 58 प्रजाति के 387 वन्य जीव-जंतु रखे गए हैं। यहाँ बब्बर शेर, घड़ियाल, हिरन, भालू, गीदड़, चीता विभिन्न प्रकार के बंदरों आदि जानवरों के लिये बाड़े और गुफा बनाए गए हैं। मछलियों के लिये एक्वेरियम भी बनाए गए हैं।
- इसके अलावा प्राणी उद्यान में एशिया के विभिन्न देशों से आने वाली रंग-बिरंगी तितलियों के लिये भी घर बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार है कि किसी प्राणी उद्यान में तितलीघर बनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च, 2021 को गोरखपुर ज़िले में पूर्वांचल के एकमात्र प्राणी उद्यान 'अशफाक उल्ला खाँ प्राणी उद्यान' का लोकार्पण किया था।

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को मिला सातवाँ स्थान

चर्चा में क्यों ?

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स- 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 7वाँ स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावी तुलना करने के लिये 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा 9 केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
- 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक 01 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि तेलंगाना (17.66 अंक) दूसरे और हरियाणा (16.35 अंक) तीसरे स्थान पर हैं।

नोट :

- प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 22 अंक के साथ 7वें स्थान पर है, ओडिशा 11.42 अंक के साथ 16वें और छत्तीसगढ़ 10.97 अंक के साथ 17वें (अंतिम) स्थान पर हैं।
- पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 37 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। इस श्रेणी में उत्तराखंड (17.67 अंक) दूसरे स्थान पर, जबकि नगालैंड (11.00 अंक) सबसे निचले पायदान पर है। दूसरी ओर केंद्रशासित प्रदेशों व शहर-राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ (27.88 अंक) को शीर्ष स्थान, जबकि लद्दाख (5.91 अंक) को अंतिम स्थान मिला है।
- उल्लेखनीय है कि नीति आयोग और प्रतिस्पर्द्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक माध्यम है। यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन को क्रम में रखता है, ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बनी रहे।
- इस इनोवेशन इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज़ पर तैयार किया गया है। पिछले संस्करणों में 36 संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया गया था, लेकिन इस बार 66 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया। पहले और दूसरे इनोवेशन इंडेक्स क्रमशः अक्टूबर 2019 तथा जनवरी 2021 में जारी किये गए थे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के हित में कदम उठाते हुए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया। अब प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी कैशलेस इलाज की व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश इस योजना को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के 22 लाख सेवारत एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अब इलाज में हुए अपने व्यय के भुगतान के लिये अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
- सरकार ने यह व्यवस्था राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिये भी शुरू की है, यानी इस योजना से करीब 75 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- इस योजना से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा उनके परिवार को आयुष्मान योजना में पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी।
- उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से राज्य कर्मचारियों, पेंशनर्स तथा उनके आश्रितों को सभी मेडिकल कॉलेजों, सरकारी अस्पतालों एवं आयुष्मान भारत में पंजीकृत निजी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये निर्यात पर ज़ोर

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्यात बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है तथा इसके तहत कार्ययोजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि निर्यात पिछले साल के21 लाख करोड़ रुपए से 30 प्रतिशत बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में इस आँकड़े को 2 लाख करोड़ रुपए करने का है।
- उन्होंने कहा कि यह पहचानने का प्रयास किया गया है कि किन उत्पादों में निर्यात की संभावनाएँ हैं, किस ज़िले में कौन-से प्रमुख उत्पाद हैं आदि। राज्य स्तर पर ऐसे 15 सेक्टरों का चयन किया गया है। जिन उत्पादों का निर्यात किया गया है, उनके अलावा उन उत्पादों की भी पहचान की गई है, जिन्हें थोड़े और प्रयास से निर्यात योग्य बनाया जा सकता है।
- हर ज़िले में ज़िला निर्यात योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही डीएम की अध्यक्षता में ज़िला निर्यात समितियों का भी गठन किया गया है। हर महीने एक बैठक होगी और विभाग को स्थानीय स्तर पर निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाएगा।

- एमएसएमई (MSME) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि निर्यातकों को विदेशी खरीदारों के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा विदेशों में आयोजित होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रदेश के निर्यातकों को विदेश में लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में भेजने की भी योजना बनाई गई है।
- एमएसएमई विभाग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, वाहन और वाहन उपकरण, रत्न और आभूषण, कार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात लेख, परिधान (साड़ी सहित), फर्नीचर, चमड़े और चमड़े के उत्पाद, खेल के सामान, काँच और काँच के बने पदार्थ, इत्र, सिरेमिक, कालीन और हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित है।
- प्रवक्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी)' निर्यात में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अन्य देशों के दूतावासों में भी सरकार द्वारा ओडीओपी की ब्रांडिंग की जाएगी। ओडीओपी उत्पादों को दूतावासों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। निर्यात बढ़ाने के लिये उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष 'उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम' के बजट को दोगुना कर दिया है। इस योजना के लिये 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह 'त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना' के तहत सब्सिडी देने के लिये इस वर्ष बजट को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित 31 प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिये कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। नई पीढ़ी को इसके महत्त्व से अवगत कराने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र के कई किलों में विशाल परिसर हैं और ये बेहतरीन होटलों में तब्दील हो सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने कालिंजर किला का जिक्र करते हुए कहा कि 542 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में कालिंजर किला स्थित है। उन्होंने अधिकारियों से निजी भागीदारी के साथ लाइट एंड साउंड शो, कैंपिंग, ट्रेकिंग, रॉक-क्लाइंबिंग और मुखौटा प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था करने के लिये कहा।
- उन्होंने जीर्ण-शीर्ण स्थिति में आ चुके किलों को पुनर्जीवित करने और तालबेहट दुर्ग एवं बरुआ सागर सरोवर में स्थित सरोवर के लिये जल क्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
- उन्होंने अधिकारियों से बहाली कार्य के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) फंडिंग मॉडल अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मॉडल भी उपयोगी हो सकता है और राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिये फंड भी देगी।

उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये निर्यात पर ज़ोर

चर्चा में क्यों?

24 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्यात बढ़ाने पर ज़ोर दिया जा रहा है तथा इसके तहत कार्ययोजना बनाकर काम शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि निर्यात पिछले साल के21 लाख करोड़ रुपए से 30 प्रतिशत बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में इस आँकड़े को 2 लाख करोड़ रुपए करने का है।
- उन्होंने कहा कि यह पहचानने का प्रयास किया गया है कि किन उत्पादों में निर्यात की संभावनाएँ हैं, किस ज़िले में कौन-से प्रमुख उत्पाद हैं आदि। राज्य स्तर पर ऐसे 15 सेक्टरों का चयन किया गया है। जिन उत्पादों का निर्यात किया गया है, उनके अलावा उन उत्पादों की भी पहचान की गई है, जिन्हें थोड़े और प्रयास से निर्यात योग्य बनाया जा सकता है।

नोट :

- हर ज़िले में ज़िला निर्यात योजना पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही डीएम की अध्यक्षता में ज़िला निर्यात समितियों का भी गठन किया गया है। हर महीने एक बैठक होगी और विभाग को स्थानीय स्तर पर निर्यातकों के सामने आने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाएगा।
- एमएसएमई (MSME) विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि निर्यातकों को विदेशी खरीदारों के साथ सीधे जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा विदेशों में आयोजित होने वाले मेलों और प्रदर्शनियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। प्रदेश के निर्यातकों को विदेश में लगने वाले मेलों और प्रदर्शनियों में भेजने की भी योजना बनाई गई है।
- एमएसएमई विभाग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, वाहन और वाहन उपकरण, रत्न और आभूषण, कार्बनिक रसायन, लोहा और इस्पात लेख, परिधान (साड़ी सहित), फर्नीचर, चमड़े और चमड़े के उत्पाद, खेल के सामान, काँच और काँच के बने पदार्थ, इत्र, सिरेमिक, कालीन और हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित है।
- प्रवक्ता ने कहा कि प्रोजेक्ट 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी)' निर्यात में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अन्य देशों के दूतावासों में भी सरकार द्वारा ओडीओपी की ब्रांडिंग की जाएगी। ओडीओपी उत्पादों को दूतावासों में भी प्रदर्शित किया जाएगा। निर्यात बढ़ाने के लिये उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये इस वर्ष 'उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम' के बजट को दोगुना कर दिया है। इस योजना के लिये 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह 'त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना' के तहत सब्सिडी देने के लिये इस वर्ष बजट को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

बुंदेलखंड में 31 प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

चर्चा में क्यों?

23 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित 31 प्राचीन किलों को नए पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिये कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। नई पीढ़ी को इसके महत्त्व से अवगत कराने की ज़रूरत है। इस क्षेत्र के कई किलों में विशाल परिसर हैं और ये बेहतरीन होटलों में तब्दील हो सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने कालिंजर किला का जिक्र करते हुए कहा कि 542 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में कालिंजर किला स्थित है। उन्होंने अधिकारियों से निजी भागीदारी के साथ लाइट एंड साउंड शो, कैंपिंग, ट्रेकिंग, रॉक-क्लाइंबिंग और मुखौटा प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था करने के लिये कहा।
- उन्होंने जीर्ण-शीर्ण स्थिति में आ चुके किलों को पुनर्जीवित करने और तालबेहट दुर्ग एवं बरुआ सागर सरोवर में स्थित सरोवर के लिये जल क्रीड़ा एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने की योजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
- उन्होंने अधिकारियों से बहाली कार्य के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) फंडिंग मॉडल अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) मॉडल भी उपयोगी हो सकता है और राज्य सरकार जरूरत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिये फंड भी देगी।

हिरासत में हुई मौतों में उत्तर प्रदेश अव्वल

चर्चा में क्यों?

27 जुलाई, 2022 को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो सालों में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।

प्रमुख बिंदु

- 2020-21 में उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में 451 मौतें दर्ज की गईं, जबकि 2021-22 में यह संख्या बढ़कर 501 हो गई। 2020-22 के दौरान उत्तर प्रदेश में 955 मौतें हिरासत में हुईं।

नोट :

- सरकारी आँकड़ों के अनुसार भारत में हिरासत में होने वाली मौतों की कुल संख्या 2020-21 में 1,940 से बढ़कर 2021-22 में 2,544 हो गई है।
- केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुस्समद समदानी के एक सवाल के जवाब में डेटा पेश करते हुए ये आँकड़े बताए।
- उत्तर प्रदेश के बाद हिरासत में सबसे ज्यादा मौतें पश्चिम बंगाल में हुईं। राज्य में 2020-21 में 185 मौतें और 2021-22 में 257 मौतें दर्ज की गईं।
- आँकड़ों के अनुसार पिछले दो सालों में बिहार में पुलिस हिरासत में कुल 396, मध्य प्रदेश में 364 और महाराष्ट्र में 340 मौतें हुई हैं।
- जम्मू-कश्मीर पुलिस मुठभेड़ों में मौत से संबंधित मामलों में दर्ज मामलों की सूची में 2021-22 में 45 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। सूची में दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, जिसमें 30 मौतें पुलिस मुठभेड़ में हुई हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 27 लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं।
- गौरतलब है कि देश भर में 2021-22 और 2020-21 में पुलिस एनकाउंटर में मौत से संबंधित कुल 151 और 82 मामले दर्ज किये गए हैं।

'एक तहसील एक उत्पाद' योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना की सफलता के बाद 'एक तहसील एक उत्पाद' योजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके ज़रिये तहसील स्तर पर प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं को नए रोज़गार मिलेंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई विभाग इस संबंध में कार्य कर रहा है। पहले चरण में ज़िले के स्थानीय प्रशासन से मिलकर तहसीलवार खास उत्पादों की सूची तैयार करेगा।
- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर तहसीलों या उनके किसी खास कस्बे का कोई उत्पाद उनकी पहचान है, जैसे- गोरखपुर के कैंपियरगंज के रमचौरा के कच्चे केले, फरेंदा महराजगंज की हरी मटर, हरदोई के संडीला का लड्डू, कुशीनगर के दुदही ब्लॉक में हल्दी की खेती आदि।
- यह संभावना है कि ODOP की तर्ज़ पर अगर इन उत्पादों की पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ज़रूरत के मुताबिक पूंजी की उपलब्धता और इनसे जुड़े लोगों के कौशल को निखारने के लिये प्रशिक्षण आदि की सुविधाएँ उपलब्ध करा दी जाएँ तो इनकी भी संभावनाएँ ODOP (One District One Product) की तरह ही बढ़ जाएंगी।
- वक्त के साथ इन उत्पादों के ज़रिये ब्रांड यूपी देश-दुनिया में और मज़बूत होगा। एक तरीके से यह 'एक ज़िला, एक उत्पाद' का ही विस्तार होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में 24 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस की शुरुआत करते हुए ODOP योजना लॉन्च की थी, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इसलिये राज्य सरकार ने 'एक तहसील एक उत्पाद' योजना पर काम करने का निर्णय लिया है।

प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिये स्टेशनरी फ्री, बैंक अकाउंट में मिलेंगे अब 1200 रुपए

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में बच्चों के लिये स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिये दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट बैठक में प्राइमरी स्कूलों के कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के अभिभावकों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस बार 1100 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए डीबीटी के ज़रिये दिये जाएंगे।

- इस राशि से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों और अशासकीय सहायताप्राप्त प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यार्थियों के लिये उनके अभिभावक वर्तमान शैक्षिक सत्र में यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते-मोजे के साथ स्टेशनरी भी खरीद सकेंगे।
- स्टेशनरी में चार कापियाँ, दो पेंसिल, दो पेन, चार रबर और चार शॉपनर शामिल हैं।
- वर्तमान शैक्षिक सत्र में दो करोड़ बच्चों के नामांकन लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 91 करोड़ बच्चे नामांकित हो चुके हैं। नामांकित बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए की रकम भेजने पर कुल 2225.6 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
- कैबिनेट ने प्रत्येक वर्ष में केंद्रांश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बिना बच्चों को यूनिफार्म, स्वेटर, बैग, जूते-मोजे और स्टेशनरी की पूरी धनराशि की अग्रिम वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव भी अनुमोदित कर दिया है। इससे यह धनराशि समय से डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खातों में भेजी जा सकेगी।
- यूनिफार्म के लिये जहाँ केंद्र व राज्य सरकार, दोनों बजट उपलब्ध कराते हैं, वहीं स्वेटर, बैग, जूते-मोजे का खर्च राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करती है।

मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए नगरीय निकायों के लिये 'मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना' शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये उन्होंने नए बने निकाय क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे नवसृजित, विस्तारित अथवा उच्चीकृत नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिये 'मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना' प्रारंभ करने की तैयारी करें।
- यह योजना इन नवीन नगरीय क्षेत्रों में सीवरेज, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता, चौराहों का सुंदरीकरण, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक केंद्र, सड़क निर्माण, स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिये उपयोगी होगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत होने वाले कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग की जानी चाहिये। इस काम में पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता होनी चाहिये। निर्माण एवं विकास कार्यों में नवाचार प्री फैब/प्री कॉस्ट कंक्रीट निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिये।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग तथा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप 'कू' के बीच एमओयू

चर्चा में क्यों?

27 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप 'कू' के साथ एक एमओयू किया है, जिसके तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) से जुड़े प्रोडक्ट के बारे में अब पूरी जानकारी 10 भारतीय भाषाओं में भी मिलेगी।

प्रमुख बिंदु

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और 'कू' के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अप्रमेय राधाकृष्ण ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- समझौते के तहत 'कू' अपने यूज़र्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये ओडीओपी से जुड़ी सामग्री और उत्पादों का 10 भाषाओं में प्रचार-प्रसार का मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा, 'कू' कॉर्पोरेट सेक्टर में उपहार देने के लिये भी ओडीओपी के उत्पाद भी खरीदेगा।
- इस समझौते से गैर-अंग्रेज़ीभाषी कारीगरों एवं लोगों की ओडीओपी से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुँच हो जाएगी। साथ ही, प्रदेश के स्थानीय कारीगरों के पास और बड़ा बाज़ार उपलब्ध हो जाएगा। इससे उन्हें व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- 'एक ज़िला, एक उत्पाद (ओडीओपी)' योजना की दूसरे देशों के दूतावासों में भी ब्रांडिंग की जाएगी। दूतावासों में ओडीओपी के उत्पाद भी प्रदर्शित किये जाएंगे और डिस्प्ले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग वहाँ से भी आयात कर सकें। इससे ओडीओपी के उत्पादों का विदेशों में भी निर्यात बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश में पाँच साल का रोडमैप तैयार, 66 लाख महिलाओं को रोज़गार से जोड़ेगी राज्य सरकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिला सशक्तीकरण के लिये पाँच साल का रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अगले पाँच सालों में करीब 66 लाख महिलाओं को नए समूहों से जोड़ते हुए उन्हें रोज़गार से जोड़ा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- तैयार रोडमैप के तहत पाँच साल के अंदर राज्य में 5 लाख 50 हज़ार 868 नए आजीविका समूहों का गठन किया जाएगा।
- मिशन द्वारा इस बृहद लक्ष्य को पाने के लिये लक्ष्य को टुकड़ों में बाँटा गया है। इसके लिये छह माह, एक साल, दो साल और पाँच साल में समूहों को बाँट दिया गया है।
- इस लक्ष्य के पूरा होने पर ग्रामीण परिवारों में महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सीधे घर-परिवार के साथ ही गाँव और राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देने लगेगा। एक समूह में न्यूनतम 10 से 14 महिलाएँ शामिल की जाती हैं। यदि प्रति समूह 12 महिलाएँ मानें तो पाँच साल में जो नए समूह बनाए जाएंगे, उनसे सीधे तौर पर 66 लाख 10 हज़ार 416 महिलाएँ जुड़ेंगी।
- वर्तमान में राज्य में 4 लाख 81 हज़ार 793 स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत् हैं। इनमें से 3 लाख 54 हज़ार 489 समूहों को समूह की गतिविधियाँ शुरू करने के लिये अब तक चरणबद्ध तरीके से 531.73 करोड़ रुपए रिवाल्विंग फंड के रूप में दिये जा चुके हैं।
- 2 लाख 85 हज़ार 913 समूहों को कम्युनिटी निवेश फंड मुहैया कराने के साथ ही इन समूहों से जुड़ी महिलाओं को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ दिया गया है। आरएफ और सीआईएफ के अलावा एक लाख 81 हज़ार 82 समूहों को कम ब्याज पर बैंकों से ऋण भी दिलाया गया है।
- मिशन निदेशक भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि समूहों की महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को संबल प्रदान करने के लिये प्रदेश सरकार ने हाल में समूहों को कई अहम योजनाओं से जोड़ने का काम किया है।
- इन योजनाओं में प्रमुख रूप से बीसी सखी, पुष्टाहार निर्माण इकाई, उचित दर की दुकानों का आवंटन, सामुदायिक शौचालय का प्रबंधन, बिजली बिल कलेक्शन, ओजस (सोलर उत्पाद), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, मनरेगा में सहभागिता, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम, ड्राइ राशन का वितरण, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना, फार्म वैल्यू चेन आदि हैं।

उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

29 जुलाई, 2022 को 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' और 'सांस्कृतिक आदान-प्रदान योजना' के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मध्य करार (एमओयू) किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉ. लवकुश द्विवेदी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली की ओर से सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक प्रियंका मिश्रा ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किये।
- इस करार से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के मुख्यालय सहित देश में उसकी सभी संस्थाओं के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान का रास्ता खुल गया है।
- इस कड़ी में सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की गुजरात इकाई द्वारा गुजरात की रामलीला को अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में भेजने की सहमति हुई है।